





# COMMITTEES & COMMISSIONS



- P.K. Mohanty Committee
- पी. के. मोहंती समिति
- To review the extant licensing guidelines and regulations relating to ownership and control in Indian private sector banks and suggest appropriate norms.
- To examine and review the eligibility criteria
- भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित मौजूदा लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों और विनियमों की समीक्षा करना और उपयुक्त मानदंडों का सुझाव देना।
- बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्तियों / संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड की जांच और समीक्षा करना।

- Arun Goel Committee
- अरुण गोयल समिति
- For strengthening India's capital goods sector, to help them in contributing more actively towards the national goal of achieving a USD 1 trillion manufacturing setor.
- भारत के पंजीगत सामान क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर के विनिर्माण सेक्टर को प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में अधिक सक्रिय रूप से योगदान करने में उनकी सहायता करना।

- Market Data Advisory Committee (MDAC) is headed by Madhabi Puri Buch.
- माकेर डेरा एडिइजरी समिति (MDAC) की अध्यक्षता माधबी पुरी बुच ने की
- To recommend appropriate policy for access to securities market data, identify segment wise data perimeters, data needs and gaps, recommend data privacy and data access regulations applicable to market data.
- प्रतिभूति बाजार डेटा तक पहुंच के लिए उपयुक्त नीति की सिफारिश करने के लिए, खंड के अनुसार डेटा परिधि, डेटा की जरूरतों और अंतराल की पहचान करना, डेटा गोपनीयता और बाजार डेटा पर लागू डेटा एक्सेस नियमों की सिफारिश करना।

- Rajiv Mehrishi Committee
- राजीव महर्षि समिति
- To measure the impact on the national economy and financial stability of waiving of interest and COVID-19 related moratorium. To give suggestions to mitigate financial constraints of various sections of society
- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और ब्याज की छूट और COVID-19 संबंधित स्थगन की वित्तीय स्थिरता को मापने के लिए। समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय बाधाओं को कम करने के लिए सुझाव देना

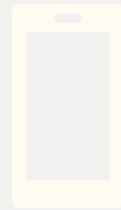
- Committee For Analysis of QR Code under the Chairmanship of D.B. Phatak
- डी.बी. की अध्यक्षता में क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए समिति फटकी
- To review the prevalent system of QR Codes in India for facilitating digital payments. Report highlighted that the government should provide incentives to popularise usage of QR code transactions among consumers.
- डिजिटल भगतान की सुविधा के लिए भारत में क्यूआर कोड की प्रचलित प्रणाली की समीक्षा करना। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को उपभोक्ताओं के बीच क्यूआर कोड लेनदेन के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।

- Raja Chelliah Committee on tax reforms 1991
- कर सुधारों पर राजा चेलिया समिति 1991
- To examine the then tax structure of the country and suggest appropriate changes therein. Its recommendations included Lowering tax rate and narrowing spread between the lowest rate and maximum marginal rate (the rate of the highest slab), Avoiding double taxation, Reducing corporate tax rate differences between domestic and foreign companies, Rationalising capital gains tax, Rationalisation of wealth tax, Tariff reduction.
- देश के तत्कालीन कर ढांचे की जांच करना और उसमें उचित बदलाव का सुझाव देना। इसकी सिफारिशों में कर की दर कम करना और न्यूनतम दर और अधिकतम सीमांत दर (उच्चतम स्लैब की दर) के बीच फैलाव को कम करना, दोहरे कराधान से बचना, घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच कॉर्पोरेट कर की दर के अंतर को कम करना, पंजीगत लाभ कर को युक्तिसंगत बनाना, धन कर का व्यक्तिकरण शामिल है। , टैरिफ में कमी।



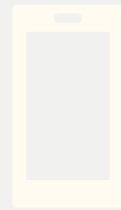
- Malegam committee on Microfinance
- माइक्रोफाइनेंस पर मालेगाम समिति
- It was set-up in 2010, to review the definition of 'microfinance' and 'Micro Finance Institutions (MFIs)' for the purpose of regulation of nonbanking finance companies (NBFCs) undertaking microfinance by the Reserve Bank of India and make appropriate recommendations.
- यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा माइक्रोफाइनेंस करने वाली गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के नियमन के उद्देश्य से 'माइक्रोफाइनेंस' और 'माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एमएफआई)' की परिभाषा की समीक्षा करने और उचित सिफारिशें करने के लिए 2010 में स्थापित किया गया था।

- Kasturirangan Committee
- कस्तूरीरंगन समिति
- New Draft of National Education Policy
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया मसौदा



- One Man (Justice Madan B. Lokur) Committee to prevent stubble burning
- पराली जलाने से रोकने के लिए वन मैन (जस्टिस मदन बी लोकर) कमेटी
- To take steps for preventing stubble burning in Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh which is a source of Pollution in the Delhi-national capital region (NCR); headed by Justice Madan B. Lokur
- पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से रोकने के लिए कदम उठाना, जो दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण का एक स्रोत है; न्यायमूर्ति मदन बी लोकुरी की अध्यक्षता में

- Abhijeet Sen Committee
- अभिजीत सेन समिति
- Formulating food policy in the long term
- लंबी अवधि में खाद्य नीति तैयार करना



- Sukhamoy Chakravarty Committee
- सुखमय चक्रवर्ती समिति
- Monetary Policy
- मौद्रिक नीति



- Khusro committee
- खुसरो समिति
- Agricultural Credit System
- कृषि ऋण प्रणाली



- Sarkaria Commission
- सरकारिया आयोग

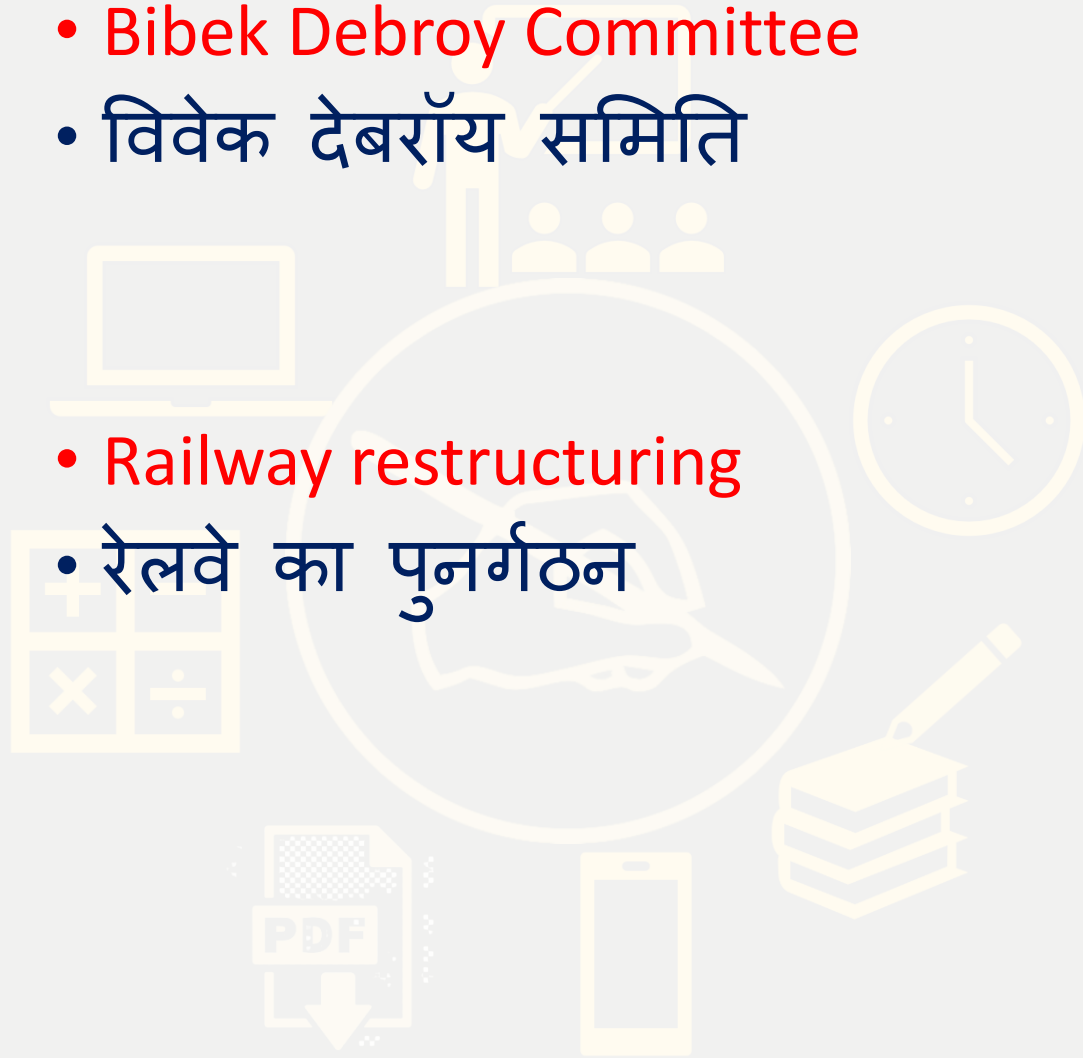
- Relationship and Power balance between the Centre and States

- केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और शक्ति संतुलन

- Lodha committee
- लोढ़ा समिति
- To recommend reforms for cricket in India
- भारत में क्रिकेट के लिए सुधारों की सिफारिश करने के लिए



- **Bibek Debroy Committee**
- विवेक देबरॉय समिति
- **Railway restructuring**
- रेलवे का पुनर्गठन



- Justice M. B. Shah Commission
- न्यायमूर्ति एम बी शाह आयोग

- Black Money

- काला धन



- Deepak Parekh Committee
- दीपक पारेख समिति
- Financing Infrastructure through PPP model
- पीपीपी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण

- Hanumant Rao Committee
- हनुमंत राव समिति
- Fertilisers
- उर्वरकों



- Janakiraman Committee
- जानकीरमन समिति
- The Janakiraman Committee was set up by Reserve Bank Of India in April 1992 to identify the irregularities that had taken place in the securities transactions
- जानकीरमन समिति की स्थापना अप्रैल 1992 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के लेन-देन में हुई अनियमितताओं की पहचान करने के लिए की गई थी।

- Kothari commission
- कोठारी आयोग

- To examine all aspects of the educational sector in India
- भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए

- N.N. Vohra Committee
- एन.एन. वोहरा समिति

- studied of the problem of criminalization of politics and the nexus among criminals, politicians, and bureaucrats in India.

- राजनीति के अपराधीकरण की समस्या और भारत में अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ का अध्ययन किया।

- Punchhi Committee
- पुंछी समिति
- Centre-State relations
- केंद्र-राज्य संबंध





- Dantwala Committee
- दंतवाला समिति
- Related to poverty estimation
- गरीबी के आकलन से संबंधित



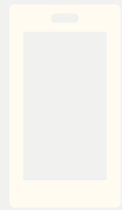
- Goiporia Committee
- गोइपोरिया समिति

- Reform of Banking Services
- बैंकिंग सेवाओं में सुधार

- Goswami Committee
- गोस्वामी समिति
- Electoral Reforms
- चुनावी सुधार

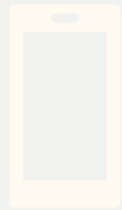


- Meera Seth Committee
- मीरा सेठ समिति
- Development of Handlooms
- हथकरघा का विकास



- Nanavati commission
- नानावती आयोग
- to investigate the "killing of innocent sikhs" during the 1984 anti-Sikh riots.
- 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान "निर्दोष सिखों की हत्या" की जांच करने के लिए।

- **Balwant Rai Mehta Committee**
- बलवंत राय मेहता समिति
- **Panchayati Raj Institutions**
- पंचायती राज संस्थान



- Suresh Tendulkar Committee

सुरेश तेंदुलकर समिति

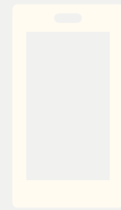
- It incorporated private expenditure on health and education in consumer expenditure while estimating poverty. (The earlier poverty estimation methods assumed that health and education were the responsibility of the and expense was not needed to be done by the consumer to access these.) It suggested targeted nutritional outcomes instead of calorie norms for the estimation of poverty.
- इसने गरीबी का आकलन करते हुए उपभोक्ता व्यय में स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय को शामिल किया। (पहले के गरीबी आकलन के तरीकों में माना जाता था कि स्वास्थ्य और शिक्षा की जिम्मेदारी थी और इन तक पहुंचने के लिए उपभोक्ता को खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी।) इसने गरीबी के आकलन के लिए कैलोरी मानदंडों के बजाय लक्षित पोषण संबंधी परिणामों का सुझाव दिया।

- **Ajit Kumar Committee**
- अजीत कुमार समिति
- **Army pay scales**
- सेना वेतनमान

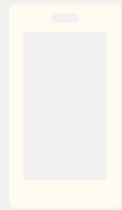




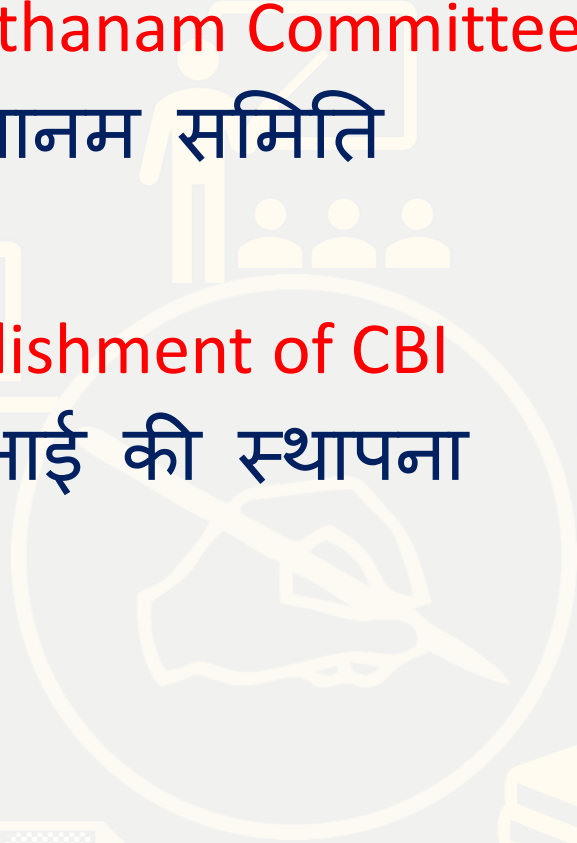
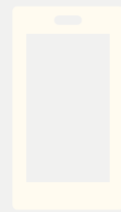
- Bhagwati Committee
- भगवती समिति
- Unemployment and Public Welfare
- बेरोजगारी और लोक कल्याण



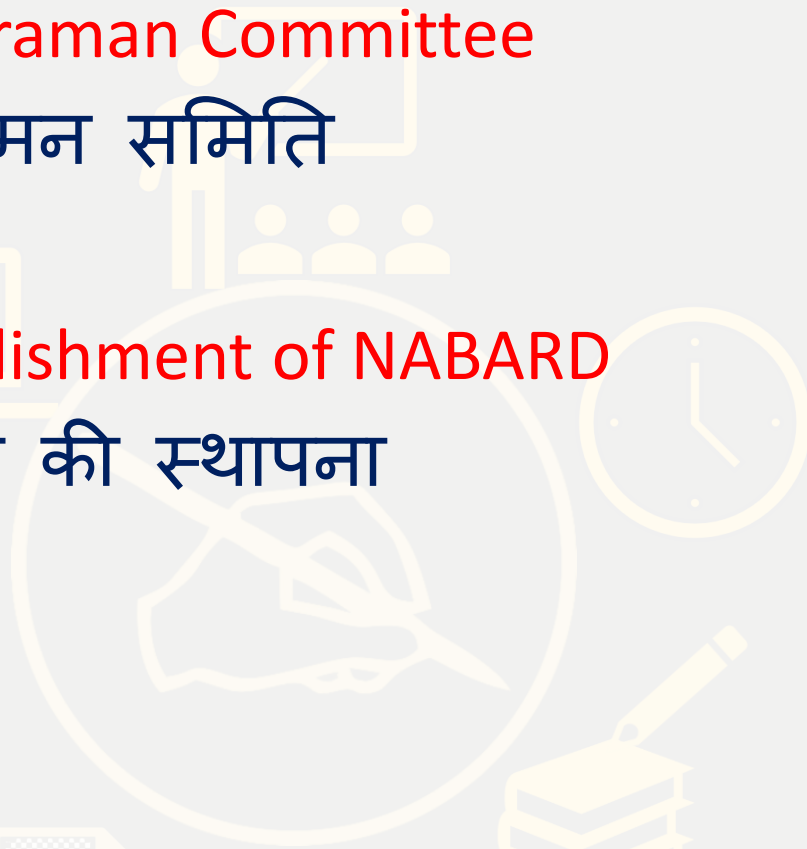
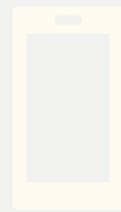
- Radha Krishnan Commission
- राधा कृष्णन आयोग
- Establishment of the University Grant Commission
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना



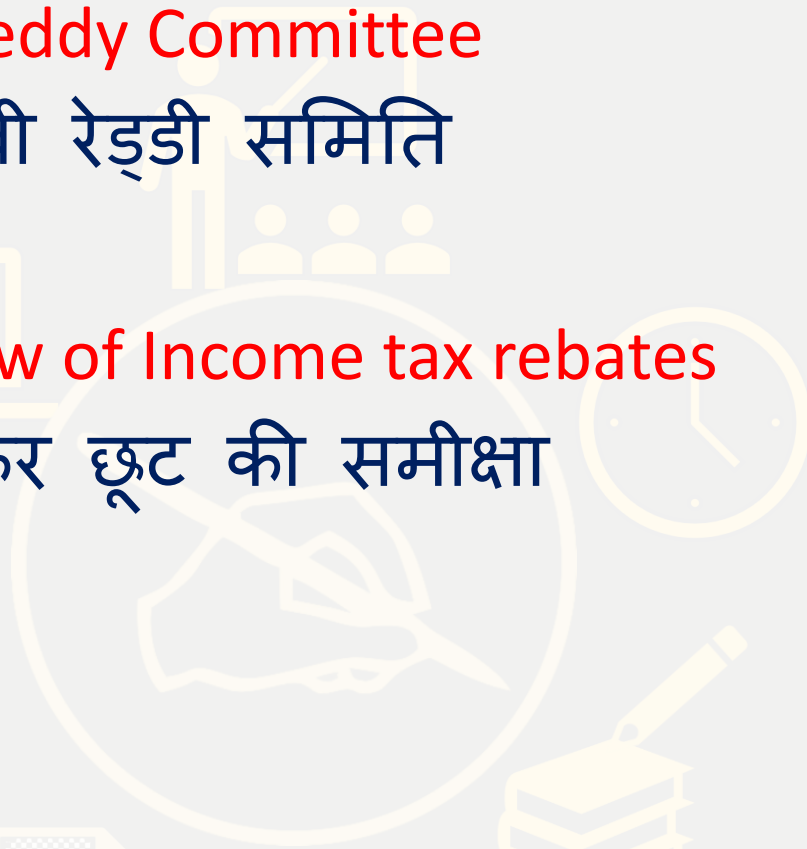
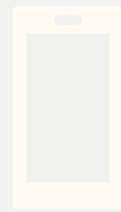
- K.Santhanam Committee
- के.संथानम समिति
- Establishment of CBI
- सीबीआई की स्थापना



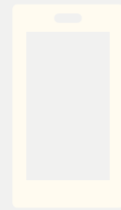
- **Shivaraman Committee**
- शिवरमन समिति
- **Establishment of NABARD**
- नाबार्ड की स्थापना



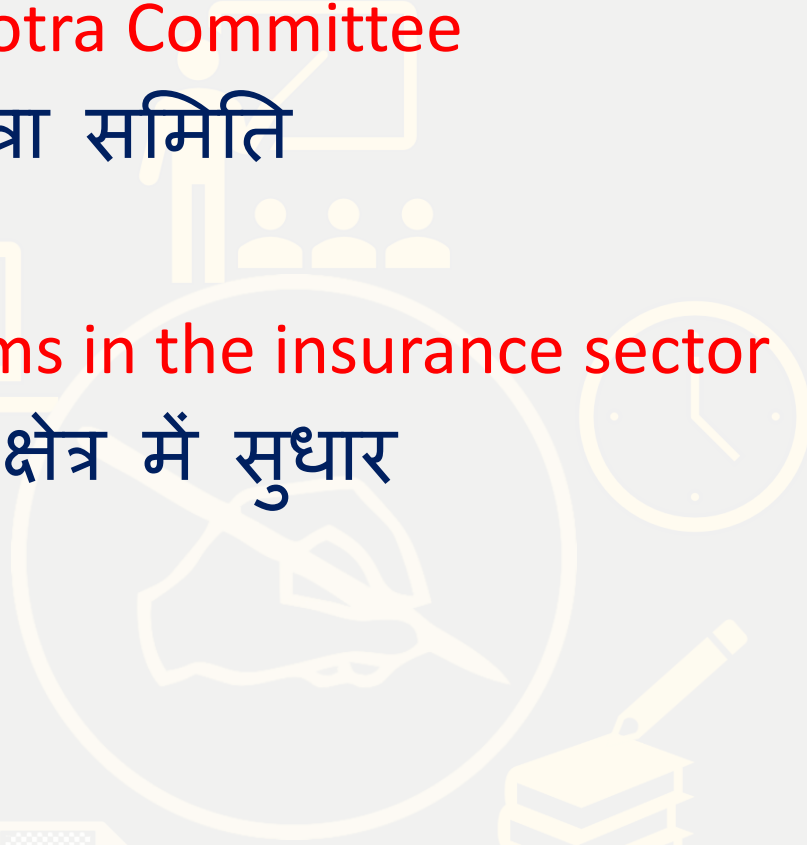
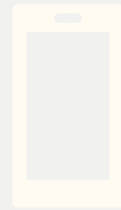
- Y V Reddy Committee
- वाई वी रेड्डी समिति
- Review of Income tax rebates
- आयकर छूट की समीक्षा



- Abid Hussain Committee
- आबिद हुसैन समिति
- Small scale industries and Trade Policy Reform
- लघु उद्योग और व्यापार नीति सुधार



- Malhotra Committee
- मल्होत्रा समिति
- reforms in the insurance sector
- बीमा क्षेत्र में सुधार



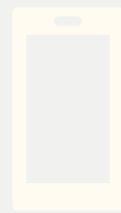
- Nanjundappa Committee Regarding
- नंजुंदप्पा समिति के संबंध में
- railway fare
- रेल किराया



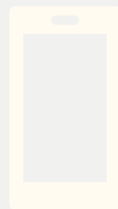


- Bhandari committee
- भंडारी समिति
- on Restructuring regional rural banks (RRBs)
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्गठन पर

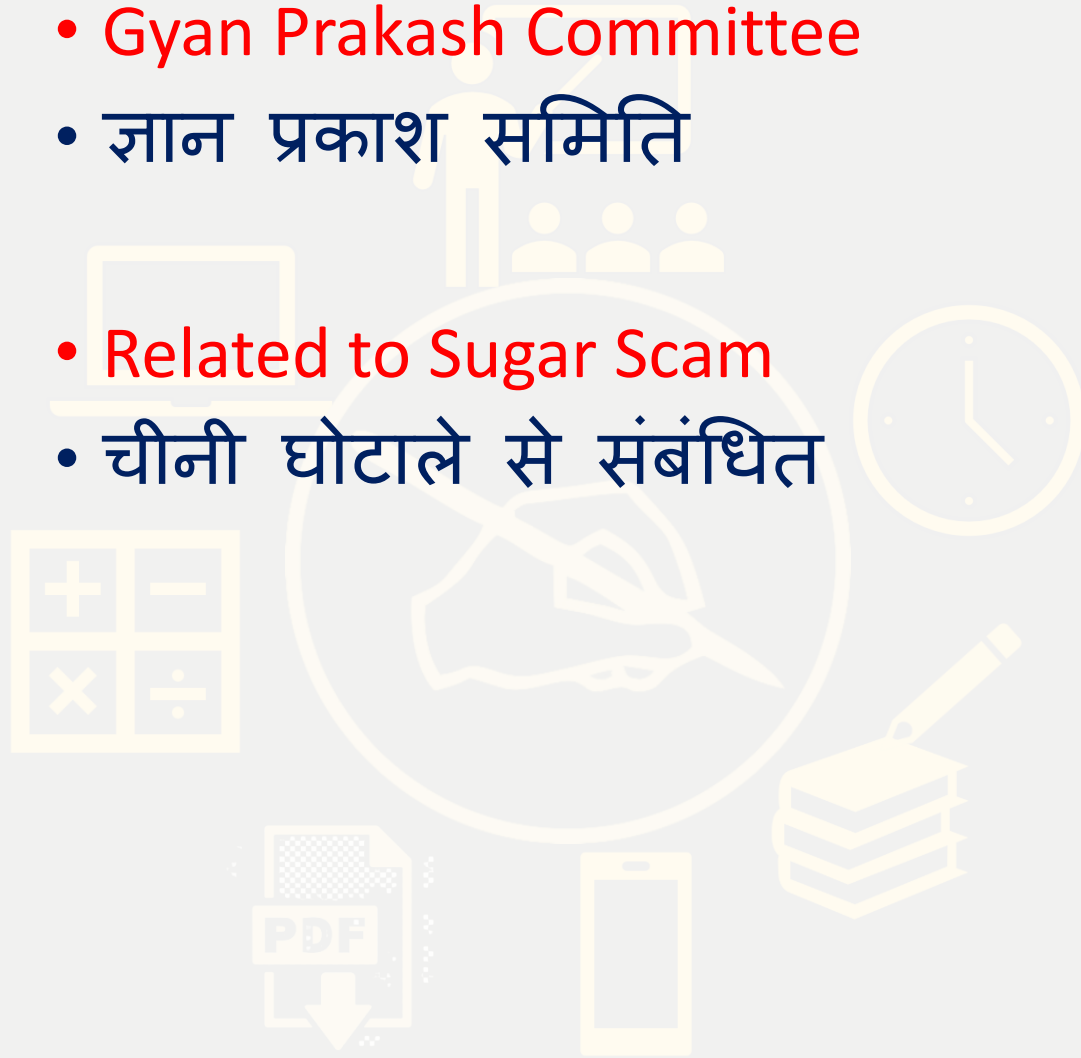
- M. G. Joshi Committee
- एम जी जोशी समिति
- Guidelines for Private Sector Entry in Telecom
- दूरसंचार में निजी क्षेत्र के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश



- Neeraj Kumar Gupta Committee
- नीरज कुमार गुप्ता समिति
- To promote cashless transactions
- कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए



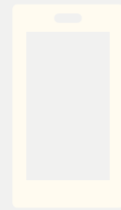
- Gyan Prakash Committee
- ज्ञान प्रकाश समिति
- Related to Sugar Scam
- चीनी घोटाले से संबंधित



- Satyam Committee
- सत्यम समिति
- Textile Policy
- कपड़ा नीति



- **Bhurelal Committee**
- भूरेलाल समिति
- **Increases in Motor Vehicle Tax**
- मोटर वाहन कर में वृद्धि



- Justice A.K Mathur Commission
- न्यायमूर्ति एके माथुर आयोग
- 7th Pay Commission
- 7 वें वेतन आयोग

